## Dainik Bhaskar (Indore), 02<sup>nd</sup> February 2025, Page- 06

## बजट पर प्रतिक्रियाएं

## आईआईटी में निवेश तकनीकी क्षेत्र के लिए अच्छा कदम

**ड**ॉ. रमेश बाहेती, उद्योगपति एवं शिक्षाविद :



आयकर के माध्यम से लोगों को जितने पैसों का लाभ दिया है, वह पैसा बाजार में ही आएगा। जिस पर जीएसटी लगेगा, उस जीएसटी से सरकार के खजाने

में वृद्धि होगी।

- सीए अनिल गर्ग: आयकर में राहत से बचत व निवेश को बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक संस्थाओं को पंजीकरण नवीनीकरण में छूट स्वागतयोग्य है। अपडेटेड रिटर्न्स दाखिल करने की अवधि 48 माह कर दी गई है।
- डॉ. मनोहर दास सोमानी, अर्थशास्त्री एवं शिक्षाविद : आईआईटी के विद्यार्थियों को पीएम स्कॉलरिशप योजना का लाभ मिलेगा। मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष 10 हजार सीटों की वृद्धि से भी इंदौर के विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई के अवसर मिलेंगे।
- डॉ. डेविश जैन, चेयरमैन, सोयाबीन

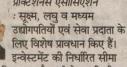


प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया: बजट तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों को सशक्त

बनाने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

• संजीव अग्रवाल, सीनियर वाइस प्रेसीडेंट — इंपेटस टेक्नोलॉजीस : यह बजट हमारी आईटी इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है। इसमें निर्यात को बढ़ावा देने और एमएसएमई सेक्टर के लिए लाभकारी प्रावधान किए गए हैं। आईआईटी में निवेश तकनीकी क्षेत्र के लिए अच्छा कदम है।  प्रो. सुहास जोशी, निदेशक, आईआईटी इंदौर
 आईआईटी इंदौर को भारत के उभरते शैक्षणिक परिदृश्य का हिस्सा होने पर गर्व है और संस्थान क्षमता में विस्तार, अनुसंधान को बढ़ावा देने और देश के तकनीकी विकास में योगदान देने की संभावनाओं को लेकर उत्साहित है।

• सीए गोविंद अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन



को ढाई गुना किया गया है। टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर दो गुना किया गया है।

- अजीत सिंह नारंग (अध्यक्ष) एवं सुरेश हरियाणी (सचिव), मालवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज: बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से देश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
- यशवंत लोभाने, कर सलाहकार : आयकर स्लैब और टीडीएस में राहत स्वागतयोग्य है। भविष्य में सोना भी प्रति 10 ग्राम एक लाख (वर्तमान में 85 हजार के आसपास) की ओर अग्रसर है। सरकार ने वर्तमान संदर्भ में पुराने नियम कानूनों में बड़े परिवर्तन किए हैं। अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक लायां जाएगा।
- आशीष वैश, अध्यक्ष, सीआईआई मध्य प्रदेश राज्य परिषद : सात अतिरिक्त टैरिफ दरों को हटाकर केवल आठ प्रमुख स्लैब रखने से

व्यापार नीति को सरल बनाया गया है जिससे मैन्युफैक्चरिंग की लागत में कमी आएगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।

• रमेश खंडेलवाल, अध्यक्ष, अहिल्या चैंबर



ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज: सीनियर सिटीजन को एक लाख तक प्राप्त ब्याज टैक्स फ्री, आयकर प्रकरण में स्क्रूटिनी के प्रकरणों को कम करने की

घोषणा, विवाद से विश्वास तक स्कीम की समय सीमा में वृद्धि बड़ी सौगात है।

- सिद्धार्थ सेठी, उपाध्यक्ष, सीआईआई मध्यप्रदेश: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश देश के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है और प्रौद्योगिकी निवेश को भी बढ़ावा दिया गया है।
- डॉ. गौतम कोठारी, अध्यक्ष, पीथमपुर औद्योगिक संगठन : बजट औद्योगिक क्षेत्र की कई प्रमुख अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हैं। कुछ क्षेत्रों में और सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। प्रस्तुत नीतियों से उद्योग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है जो आर्थिक विकास में सहायक होंगे।
- दिनेश पाटीदार, चेयरमैन, शिक्त



पंस (इंडिया) लिमिटेड : बजट इंडस्ट्री के लिए बेहद सकारात्मक है, खासकर सोलर सेक्टर के लिए। सरकार सोलर सेल्स पर खास इंसेंटिव ला रही

है, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

• सीए सोमेंद्र शर्मा: समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण सुधारों और उपायों की घोषणा की है। इसमें मध्यम वर्ग को आयकर में बड़ी राहत देने की योजनाएं शामिल हैं